

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012—ज्येष्ठ 4, शक 1934

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999) आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. (2000), संचालक, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को केवल संचालक, जनसंपर्क के प्रभार से मुक्त करते हुये, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 328/187/अव./2012/1-8/स्था.— श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-4-2012 से 5-5-2012 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-4-2012 एवं 6-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जेविहर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 330/156/अव./2012/1-8/स्था.— श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग को दिनांक 16-4-2012 से 5-5-2012 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15 एवं 6-5-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुरबिया, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु. जाति विकास विभाग के पद पर पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 332/182/अव./2012/1-8/स्था.— श्री अब्बास खान, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 16-4-2012 से 20-4-2012 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15, 21 एवं 22-4-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री खान आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.
3. अवकाश अवधि में श्री खान को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 334/196/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 18-4-2012 से 28-4-2012 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-4-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुन्दानी आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.
3. अवकाश अवधि में श्री कुन्दानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुन्दानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

क्रमांक 336/168/अव./2012/1-8/स्था.—श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-4-2012 से 5-5-2012 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22-4-2012 एवं 6-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सांकला आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.
3. अवकाश अवधि में श्री सांकला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सांकला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्रमांक 376/180/अव./2012/1-8/स्था.—श्री सैयद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 30-4-2012 से 11-5-2012 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-4-2012, 12-5-2012 एवं 13-5-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-10/2005/1-8.—राज्य शासन एतद्वारा डॉ. समरेन्द्र सिंह (प्राध्यापक) राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना सेल, उच्च शिक्षा विभाग को पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक 392/246/अव./2012/1-8/स्था.—श्री विनोद वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 2-5-2012 से 11-5-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12 एवं 13-5-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.
3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक 428/202/अव./2012/1-8/स्था.—श्री आर. के. स्वास्तिक, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 23-4-2012 से 28-4-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 21, 22 एवं 29-4-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री स्वास्तिक आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.
3. अवकाश अवधि में श्री स्वास्तिक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वास्तिक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,  
मुकुन्द जभिये, अवर सचिव.

## ऊर्जा विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. के अंतर्नियम की कंडिका 77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा श्री सुबोध कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के दिनांक 29-04-2012 से दिनांक 23-06-2012 तक प्रशिक्षण हेतु प्रवास पर रहने के कारण उक्त अवधि के लिए प्रबंध निदेशक, छ.ग. विद्युत वितरण कंपनी मर्या. का अतिरिक्त प्रभार श्री जी. एस. कलसी, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी को सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2012

क्रमांक 1002/एफ 21/01/2011/13/2/ऊ.वि.—यतः राज्य सरकार की यह राय है, कि राज्य की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (एस.ई.जेड.) नीति, 2010 के अधीन स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है.

2. अतएव, छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्रमांक 10 सन् 1949) की धारा 3-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, केन्द्रीय विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का क्र. 28) में अधिसूचित क्षेत्र में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 के खण्ड 8 के उपबंध के अनुसार पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से विद्युत के विक्रय एवं उपभोग पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट प्रदान करती है :-
  - (अ) छूट की पात्रता उन्हीं उद्यमी/विकासकर्ता/इकाई को होगी, जो उक्त अधिनियम के अधीन पात्रता रखते हैं तथा जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया हो.
  - (ब) राज्य सरकार की विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 के अधीन अधिसूचित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख तथा उक्त केन्द्रीय अधिनियम की शर्तों के पालन की पुष्टि में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अनुशंसा व पात्रता प्रमाण पत्र सहित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.
  - (स) आवेदन पर विचारोपरांत, मुख्य विद्युत निरीक्षक पात्र उद्यमी/विकासकर्ता/इकाई को विद्युत शुल्क में छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी करेगा.
  - (द) छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति, 2010 एवं नियमों के अधीन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते पाये जाने पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्रता समाप्त समझी जायेगी तथा दी गई विद्युत शुल्क छूट की राशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 5 के अधीन भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जायेगी.
3. यह अधिसूचना 27 जनवरी, 2011 से प्रभावशील हुई समझी जायेगी तथा आगामी आदेश तक प्रवृत्त रहेगी.
4. इस अधिसूचना के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, किसी भी समय इस अधिसूचना में कोई संशोधन कर सकती है एवं इस अधिसूचना के उपबंधों की विसंगतियों को दूर कर सकेगी एवं किसी स्पष्टीकरण के लिए निर्देश एवं दिशा-निर्देश जारी कर सकेगी.

No. 1002/F 21/01/2011/13/2/E.D.—Whereas, the State Government is of the opinion that to promote the industrial units to be installed under the Special Economic Zone (S.E.Z.) Policy, 2010 in the State, it is necessary and expedient.

2. Now therefore, in exercise of powers conferred by Section 3-B of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949), the State Government, hereby, exempts the payment of electricity duty on sale and consumption of electricity from the date commercial production to eligible units as per provision of Clause 8 of

SEZ Policy, 2010 in the area notified in Central Special Economic Zone Act, 2005 (No. 28 of 2005), subject to the following conditions :—

- (a) Exemption shall be extended to such entrepreneur/developer/units who are eligible under said Act and to whom the eligibility certificate has been issued from Commerce and Industry Department.
  - (b) Industries set up in Special Economic Zone notified under SEZ Policy, 2010 of State Government, shall submit application to Chief Electrical Inspector on confirmation of date of commercial production and on fulfilling the conditions of said Central Act with recommendation and eligibility certificate from Commerce & Industry Department.
  - (c) After due consideration of application, Chief Electrical Inspector shall issue electricity duty exemption certificate to the eligible entrepreneur/developer/unit.
  - (d) Eligibility for exemption from payment of electricity duty shall deemed to be cancelled on violation of conditions stipulated under the Chhattisgarh State Special Economic Zone Policy, 2010 and Rules and exempted electricity duty shall be recovered with interest accruing thereon, if any, as an arrears of land revenue under section 5 of the Electricity Duty Act, 1949.
3. This notification shall be deemed to have come into effect from 27th January, 2011 and shall remain in force till further order.
  4. Notwithstanding anything contained in any other provision of this notification, the State Government, may at any time make any amendment in this notification and issue instructions and guidelines to facilitate the implementation of, remove anomalies in and provide clarifications to the provisions of this notification.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

### श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-6/2012/16.— भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है :—

#### मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना :—

##### (अ) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना—

- (i) यह योजना “मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना” कहलाएगी.
- (ii) यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी.
- (iii) यह योजना भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22(1) सहपठित छत्तीसगढ़ नियम, 2008 के नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी.
- (iv) यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय-पत्र धारी हैं.

##### (ब) परिभाषाएं— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (i) “अधिनियम” से आशय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है.

- (ii) "बोर्ड" से आशय धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।
- (iii) "सचिव" से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।
- (iv) "दुर्घटना" से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते-जाते समय अथवा अन्य किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से है।
- (v) "आश्रित" से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, आश्रित माना जावेगा—  
—पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)  
—अवयस्क पुत्र  
—अविवाहित पुत्री  
—पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे  
—आश्रित माता-पिता
- (vi) "परिवार" से आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे सम्मिलित माने जाएंगे।
- (vii) "नामिति" अथवा "नामित" से आशय हिताधिकारी निर्माण श्रमिक द्वारा छत्तीसगढ़ नियम, 2009 के नियम 44(4) के अंतर्गत नाम निर्देशित किए गए नामिति से है।
- (viii) "निगम" से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
- (ix) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना-मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रवर्तित जनश्री बीमा योजना से है और इसमें निगम द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधन भी शामिल है।

परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वहन-उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है।

(स) योजना का विवरण :—

- (i) निर्माण श्रमिकों को धारा 22(1) सहपठित राज्य नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे केवल निगम कहा जावेगा) के सहयोग से मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन बीमा द्वारा निर्धारित समस्त अनुलाभों सहित प्रभावशील होगी।
- (ii) पात्रता —  
  - (1) 18 से 59 वर्ष की आयु समूह के निर्माणी श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  - (2) हिताधिकारी के रूप में मण्डल में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों का इस योजना के अंतर्गत बीमा हो सकेगा।
  - (3) समूह की पात्रता और अधिसूचना जीवन बीमा निगम द्वारा नोटल एक्सेसी अर्थात् बोर्ड की सलाह से निर्धारित की जाएगी।
  - (4) बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों, जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा, के लिए यह योजना प्रवर्तित होगी।
- (iii) हितलाभ—  
  - (1) सदस्य की सामान्य मृत्यु पर रुपये 30,000/-
  - (2) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 75,000/-
  - (3) दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर रुपये 75,000/-

(4) दुर्घटना में एक अंग या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रुपये 37,500/- का लाभ श्रमिक/आश्रित को दिया जाएगा.

1. हिताधिकारी जब स्वयं को क्षति पहुंचाये, आत्महत्या (स्वघात) हो एवं अत्यधिक शराब के सेवन करने से मृत्यु होने पर,
2. पर्वतारोहण करते हुए, शिकार करते हुए, दंगा करते हुए, युद्ध करते हुए, (अघोषित युद्ध) हुल्लड़ करते हुए,  
(क्रमांक 1 एवं 2 की दशा में मृत्यु पर दुर्घटना मृत्यु का लाभ नहीं मिलेगा अपितु सामान्य मृत्यु पर योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा)

(iv) प्रीमियम राशि-प्रत्येक सदस्य के लिए रुपये 200/- वार्षिक प्रीमियम होगा जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् 100 जीवन बीमा निगम द्वारा वहन की जावेगी.

(v) नोडल एजेंसी-हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के संबंध में बोर्ड नोडल एजेंसी होगा तथा बोर्ड एवं जीवन बीमा निगम द्वारा सभी परिचय-पत्र धारी श्रमिकों की ओर से बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जावेंगी.

**(द) दावा कार्य प्रणाली :-**

- (i) बीमित मृत सदस्य के नामित या आश्रित को मृत्यु प्रमाण-पत्र की मूल प्रति अन्य विवरण सहित प्रपत्र-एक में नोडल एजेंसी (जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी) को देनी होगी. नोडल एजेंसी द्वारा दावा फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में भेजते हुए बोर्ड को अवगत करायेगा तथा भारतीय जीवन निगम द्वारा दावे का निपटारा एकाउण्ट पेयी चेक बोर्ड के नाम से जारी कर किया जावेगा.
- (ii) दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में उपयुक्त विवेचना तथा प्रमाणिकता साबित होने पर बोर्ड द्वारा बीमित अथवा आश्रित या नामित को देय दावा राशि के अधिकतम 50 प्रतिशत राशि का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक से किया जा सकेगा शेष दावा राशि का भुगतान बीमित या नामित को, निगम से दावे का भुगतान प्राप्त होने पर किया जावेगा.
- (iii) श्रम विभाग के जिला कार्यालय में बीमित सदस्यों से दावा प्रार्थना पत्र और शिक्षा सहयोग योजना के आवेदन प्राप्त करने, उनकी जांच करने और दावा राशि का भुगतान संबंधित को करने के लिए बोर्ड की ओर से अधिकृत एजेंसी होंगे. बोर्ड द्वारा अन्य किसी विभाग के कार्यालयों को अधिकृत एजेंसी बनाया जा सकेगा.

(इ) अन्य लाभ— शिक्षा सहयोग का लाभ-मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना के धारकों को दो बच्चों तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए 100/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जावेगी. शिक्षा सहयोग योजनान्तर्गत हिताधिकारी को अथवा नोडल एजेंसी (बोर्ड) का कोई पृथक, प्रीमियम नहीं होगा.

(ई) मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना की प्रक्रिया— बोर्ड द्वारा प्रदेश में पंजीबद्ध किए गए निर्माण श्रमिकों की सूची, जिसमें निर्माण श्रमिकों का नाम, आयु तथा उनके नामांकितों (आश्रितों) का पता सम्मिलित होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम को समूह के निर्माण श्रमिकों को जनश्री बीमा योजना की परिधि में लाने के लिए उपलब्ध करायी जावेगी तथा निर्माण श्रमिकों के मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर बीमा योजना हेतु 100/- प्रति सदस्य प्रीमियम बोर्ड द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अदा किया जाएगा.

(फ) विसंगति का निराकरण— योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक ढांड, प्रमुख सचिव.



रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 10-6/2012/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गई सारणी में कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कर्मकारों के निम्नलिखित प्रवर्ग को असंगठित कर्मकार के रूप में सम्मिलित करती है :—

क्रमांक	कर्मकार का नाम
41.	नट-नटनी
42.	देवार
43.	शिकारी
44.	अन्य घुमन्तु जाति
45.	खैरवार
46.	रसोईयां
47.	हड्डी बीनने वाले (हड्बिन्ने)
48.	काष्ठागार में काम करने वाले हम्माल
49.	समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर)

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 10-7/2012/16.—राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित करने हेतु भूमि धारण करने की सीमा, निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

“2.5 एकड़ अथवा उससे कम कृषि योग्य भूमि धारण करने वाले कृषक अथवा खेतीहर मजदूर को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत असंगठित कर्मकार माना जावेगा”

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 10-8/2012/16.—राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2(K) एवं (N) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असंगठित कर्मकार के रूप में अधिसूचित करने हेतु आय की सीमा, निम्नानुसार निर्धारित करता है :—

“रुपये 50,000/- वार्षिक से कम आय वाले कर्मकार”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

**वाणिज्य एवं उद्योग विभाग**  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक एफ 18-13/2012/11/(6)-पार्ट.—राज्य शासन एतद्वारा नवगठित 09 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालयों हेतु अतिरिक्त 72 पदों की संरचना हेतु स्वीकृति प्रदान करता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	नवीन जिलों के अतिरिक्त पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महाप्रबंधक	15600-39100	6600	09
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	5200-20200	2800	09
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200-20200	2400	09
4.	सहायक वर्ग-2	5200-20200	2400	04
5.	सहायक वर्ग-3/स्टेनोग्राफिस्ट	5200-20200	1900	14
6.	जमादार	4750-7440	1300	09
7.	भृत्य/चौकीदार	4750-7440	1300	18
<b>योग</b>				<b>72</b>

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 285/सी.एन. 0000/9/बजट-5/वित्त/चार 2012, दिनांक 24-04-2012 द्वारा जारी की जा रही है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2012

क्रमांक 441/पं.ग्रा.वि.वि./22/2012—राज्य शासन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ निधि नियम-2011 को एतद्वारा प्रकाशित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
देवाशीष दास, सचिव.

## नियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा (32) (2) खण्ड (ड़), (च) एवं धारा 21 (1) (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा गठित "महात्मा गांधी राज्य रोजगार गारंटी निधि, छत्तीसगढ़ (MGNREGA State Employment Guarantee Fund, Chhattisgarh)" के प्रशासन एवं संचालन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है।

### 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

- 1.1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, छत्तीसगढ़ निधि नियम- 2011 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee, Chhattisgarh Fund Rules - 2011)" होगा।
- 1.2 यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषाएँ एवं संक्षिप्त रूप

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ निम्नलिखित होगी :

- 2.1 "अधिनियम" से तात्पर्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 से है।
- 2.2 "राज्य परिषद्" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित एवं छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्" से है।
- 2.3 "राज्य स्तरीय सशक्त समिति" से तात्पर्य "छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्" की नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत गठित समिति से है।
- 2.4 "रोजगार गारंटी निधि" से तात्पर्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अंतर्गत गठित निधि से है। इस निधि को विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नामों से जाना जाएगा :-
  - 2.4.1 राज्य स्तर पर : अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित "महात्मा गांधी राज्य रोजगार गारंटी निधि, छत्तीसगढ़ (MGNREGA State Employment Guarantee Fund, Chhattisgarh)" जिसे "राज्य निधि" कहा गया है।
  - 2.4.2 जिला स्तर पर : "महात्मा गांधी जिला रोजगार गारंटी निधि" जिसे "जिला निधि" कहा गया है।
  - 2.4.3 जनपद स्तर पर : "महात्मा गांधी जनपद रोजगार गारंटी निधि" जिसे "जनपद निधि" कहा गया है।
  - 2.4.4 ग्राम पंचायत स्तर पर : "महात्मा गांधी पंचायत रोजगार गारंटी निधि" जिसे "पंचायत निधि" कहा गया है।
- 2.5 "लेखा इकाई" : छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जनपद के कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को पृथक-पृथक लेखा इकाईयाँ माना गया है।
- 2.6 उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु इसमें परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

### संक्षिप्ताक्षर एवं संक्षिप्त रूप

1. डी.पी.सी.	— District Programme Co-ordinator (जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर)
2. ए.डी.पी.सी.	— Additional District Programme Co-ordinator (अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)
3. अजा/अजजा	— Scheduled Caste/ Scheduled Tribe (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)
4. पी.ओ.	— Programme Officer (कार्यक्रम अधिकारी)
5. केन्द्रीय परिषद्	— Central Employment Guarantee Council (केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद्)
6. राज्य परिषद्	— Chhattisgarh Rural Employment Guarantee Council छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्
7. एनआरईजीए	— महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
8. रो.ब.पृष्ठ	— रोकड़ बही पृष्ठ
9. स.क्र.	— सरल क्रमांक
10. Dr. (डे.)	— Debit (डेबिट)
11. Cr. (क्रे.)	— Credit (क्रेडिट)
12. एडब्ल्यूपीबी	— Annual Work Plan and Proposal of Budget (वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव)

### 3. निधियों की प्राप्ति

#### 3.1 वित्तपोषण

##### 3.1.1 राज्य निधि का वित्तपोषण निम्नानुसार होगा :-

- (क) भारत सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली राशि ।
- (ख) राज्य शासन द्वारा राज्यांश एवं स्थापना अनुदान के रूप में बजट के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि ।
- (ग) अन्य प्रासंगिक प्राप्तियाँ (Incidental Receipts)

3.1.2 अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से, राज्य शासन के प्रस्ताव और पूर्व में विमोचित की गई निधि के उपयोग के आधार पर निधि उपलब्ध होगा।

3.1.3 जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रत्येक वर्ष के 30 दिसम्बर तक भारत सरकार की वेबसाइट में लेबर बजट को निर्धारित प्रपत्रों में ऑनलाईन अद्यतन करते हुए लेबर बजट की विकासखण्डवार सूची व इसके निर्माण की प्रक्रिया का पालन किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा।

3.1.4 राज्य परिषद् द्वारा जिलों से प्राप्त लेबर बजट को परीक्षण कर, समेकित वार्षिक कार्य योजना तथा समेकित बजट प्रस्ताव भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रत्येक वर्ष जनवरी माह तक प्रेषित किया जाएगा।

3.1.5 राज्य परिषद् द्वारा बजट प्रस्ताव के साथ केंद्र सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित कार्यों के लिये पूर्व में विमोचित की गई राशि के उपयोग की जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी ।

3.1.6 राज्य शासन द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय के लिये राज्य के बजट में आवश्यक निधि का प्रावधान किया जाएगा ।

### 4. वित्तीय प्रबंधन

#### 4.1 बैंक खातों का संचालन

4.1.1 इस योजना के अंतर्गत राज्य, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जमा होने वाले धन के लिए अलग-अलग बैंक खाते खोले जाएंगे। ये खाते भारत सरकार द्वारा योजना के परिचालन हेतु जारी दिशानिर्देशों (Operational Guideline) के प्रावधानों के अधीन रहेंगे।

4.1.2 राज्य निधि से संबंधित बैंक खाते का संचालन आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं संयुक्त संचालक (वित्त) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

4.1.3 जिला स्तर पर बैंक खाते का संचालन जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के तथा जनपद स्तर पर बैंक खाते का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

4.1.4 ग्राम पंचायत स्तर पर खोले गए खाते का संचालन सरपंच एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा।

### 5. अनुदान जारी करने की पद्धति

#### 5.1 अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

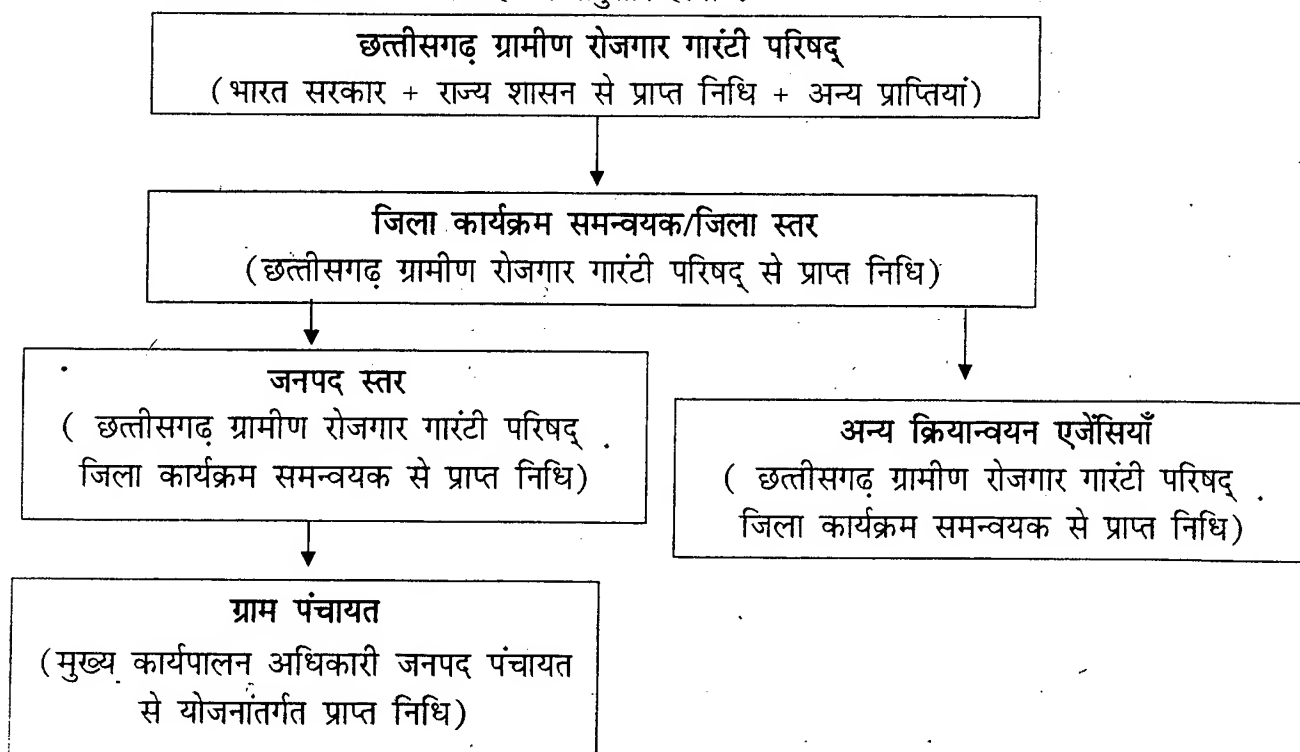
5.1.1 योजना अंतर्गत राज्य निधि, जिला निधि हेतु अनुदान/आबंटन प्राप्त करने की प्रक्रिया एक समान रहेगी।

5.1.2 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राज्य निधि में रखा जाएगा। जिसे जिले से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के आधार पर जिलों को जारी किया जाएगा।

- 5.1.3 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले को ग्रामीण विकास मंत्रालय के समक्ष एक वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव भेजना होगा जिसके आधार पर राज्य परिषद् फैसला लेगी कि संबंधित वर्ष के दौरान उस जिले को संभवतः कितनी राशि की आवश्यकता होगी।
- 5.1.4 वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव की मांग जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत श्रम बजट में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट प्रस्ताव में इस बात का भी ब्यौरा दिया जाएगा कि जिले को अब तक मिले अनुदानों का किस तरह सदुपयोग किया गया है तथा योजना के अंतर्गत प्रदर्शन के निर्धारित मानक क्या रहे हैं।
- 5.1.5 अद्यतन आबंटन/अनुदान के 50 प्रतिशत अंश का सदुपयोग कर लेने के बाद, जिला कार्यक्रम समन्वयक राज्य निधि से अगली किश्त जारी किए जाने के लिए आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर देगा तथा 60 प्रतिशत व्यय होने पर परिषद् के पास अनुदान के लिए आवेदन करेगा। यह प्रस्ताव योजना के परिचालन दिशा-निर्देश में विहित प्रारूप में होगा। अगली किश्त कंडिका 5.4 में वर्णित शर्तों के पूर्ण करने पर जारी की जाएगी।
- 5.1.6 भारत सरकार के निर्देशानुसार किश्त के प्रस्ताव ऑनलाईन भी प्रेषित किए जा सकेंगे। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- 5.1.7 राज्य परिषद् अनुदानों के दुरुपयोग के आधार पर किसी क्रियान्वयन एजेंसी को मिलने वाली सहायता रद्द कर सकती है। उस एजेंसी को मिलने वाली सहायता तभी बहाल की जाएगी जब राज्य परिषद् इस बारे में संतुष्ट हो जाएगी कि संबंधित एजेंसी द्वारा त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं।
- 5.1.8 जिला कार्यक्रम समन्वयक अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को अनुदान जारी करेगा। स्वीकृत राशि की जानकारी सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनिवार्यतः दी जाएगी।
- 5.1.9 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को किसी जिले द्वारा अनुदान का समुचित उपयोग न किए जाने की स्थिति में किसी अन्य जिले को जिसे अनुदान की तत्काल आवश्यकता है, अस्थायी रूप से सशक्त समिति के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा सकेगा। यह अनुदान राशि भविष्य में समायोजन योग्य रहेगी।

## 5.2 निधि का प्रवाह

योजनांतर्गत निधियों का प्रवाह निम्नानुसार होगा :-



### 5.3 अनुदान की पात्रता

5.3.1 उपलब्ध अनुदान/आबंटन के 60 प्रतिशत का उपयोग होते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुदान/आबंटन प्राप्त करने के पात्र होंगे।

### 5.4 किशत/अनुदान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक निर्देश

किशत/अनुदान प्रस्ताव प्रेषित करते समय निम्न तथ्यों का अवश्य ध्यान रखा जाये :-

- 5.4.1 उपलब्ध राशि के 60 प्रतिशत का उपयोग होते ही प्रस्ताव तत्काल राज्य परिषद् को भेजा जाएगा।
- 5.4.2 विगत वित्तीय वर्ष एवं इस वर्ष के विगत माह तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये। उपयोगिता प्रमाण पत्र में उपलब्ध निधि, प्रतिशत व्यय तथा शेष उपलब्ध राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- 5.4.3 जारी वित्तीय वर्ष का जिले का श्रम बजट प्रस्तुत किया जाए।
- 5.4.4 यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय श्रम बजट से अधिक हो रहा हो तो उसका समुचित कारण प्रस्तुत किया जाए।
- 5.4.5 विगत वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जिसमें समस्त क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोगिता तथा अंतिम शेष का सही-सही व स्पष्ट उल्लेख हो।
- 5.4.6 यह सुनिश्चित किया जाये कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम शेष व इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष एक समान हों।
- 5.4.7 एम.आई.एस. में डाटा निरंतर अद्यतन रखे जायें। यह सुनिश्चित किया जाये कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा एम.आई.एस. डाटा में अंतर न हो।
- 5.4.8 प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाएंगे :-
  - (i) उपलब्ध निधि का उपयोग किसी अन्य योजना में न करने संबंधी No Diversion of Fund प्रमाण पत्र।
  - (ii) राशि का दुरुपयोग न होने संबंधी No Embezzlement of Fund प्रमाण पत्र।
  - (iii) जिले में विलंबित भुगतान न होने के संबंध में प्रमाण पत्र।
  - (iv) लोकपाल की नियुक्ति, शिकायतों का निराकरण तथा राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण की अद्यतन स्थिति।
  - (v) राज्य परिषद् एवं भारत सरकार द्वारा पूर्व में चाही गई कोई अन्य जानकारी अथवा स्पष्टीकरण।
  - (vi) समस्त संलग्न दस्तावेजों की चेकलिस्ट।
- 5.4.9 प्रस्तावित राशि का उल्लेख करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र।
- 5.4.10 उक्त समस्त दस्तावेज स्कैन कराकर ई-मेल द्वारा भी प्रेषित किए जायेंगे।

### 6. व्यय एवं भुगतान

6.1.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार निम्नलिखित व्यय वहन करेगी :

- (क) अकुशल शारीरिक श्रमिकों के वेतन की पूरी लागत।
- (ख) कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के वेतन तथा भौतिक लागतों का 75 प्रतिशत अंश।
- (ग) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक पर प्रशासकीय खर्च। इनमें संचिदा या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारियों तथा उनके सहायककर्मियों के वेतन व भत्ते के साथ-साथ कार्यस्थल पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का खर्चा भी शामिल होगा।

6.1.2 राज्य सरकार निम्नलिखित व्यय वहन करेगी :-

- (क) कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों के वेतन तथा सामग्री व्यय का 25 प्रतिशत अंश।

## 6.2 रोजगार गारंटी निधि के संचितरण अधिकारी नीचे अंकित अनुसार होंगे :-

- राज्य स्तर पर :- आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं संयुक्त संचालक (वित्त)
- जिला स्तर पर :- जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
- जनपद स्तर पर :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- सरपंच एवं सचिव संयुक्त रूप से

## 6.3 रोजगार गारंटी निधि के धनादेश के निधिपाल (Custodian) नीचे अंकित अनुसार होंगे :-

- राज्य स्तर पर :- लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, राज्य परिषद्
- जिला स्तर पर :- लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
- जनपद स्तर पर :- लेखापाल, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- पंचायत सचिव

## 6.4 समस्त वसूलियाँ एवं भुगतान संचितरण अधिकारी की जिम्मेदारी पर एवं उनके द्वारा किए गए माने जाएंगे।

## 6.5 निधि से संव्यवहार हेतु प्रत्येक अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त तथा भुगतान की गई राशि की लेखों में दैनिक प्रविष्टि एवं लेखों की शुद्धता के बारे में पूर्णरूपेण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

## 6.6 योजना के अंतर्गत निधि प्राप्त करने वाला अधिकारी, जब तक निधि का लेखा राज्य परिषद् को उसकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत नहीं करता, निधि के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। भुगतान अधिकृत व्यक्तियों को ही किया गया है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उसी अधिकारी की होगी।

## 6.7 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा

## 6.8 यदि प्रदाय आदेश (Supply Order) में प्रावधानित हो, तो मुख्यालय से बाहर के भुगतान बैंक ड्रॉफ्ट से भी किए जा सकते हैं।

## 6.9 रुपये 500 एवं उससे अधिक के सभी भुगतान धनादेश के माध्यम से किए जाएंगे।

## 6.10 रुपये 1000 एवं उससे अधिक के सभी धनादेशों को रेखांकित कर 'एकाउंट पेयी' (Account Payee) अंकित किया जाएगा।

## 7. लेखा प्रणाली

सभी लेखा इकाईयों में इस योजना के संधारण के लिए पृथक से कैश बुक, लेजर, धनादेश निर्गमन पंजी, बैंक समाशोधन पंजी, आय-व्यय पत्रक, बैलेंस शीट एवं इससे संबंधित समस्त आवश्यक पंजियाँ संधारित की जाएगी, जिनमें से कुछ का प्रारूप परिशिष्ट-1 में प्रदर्शित है।

### 7.1 लेखांकन

#### 7.1.1 योजनान्तर्गत लेखा दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अनुसार संधारित किया जाएगा।

#### 7.1.2 योजना की मुख्य गतिविधियाँ श्रमिकों को रोजगार प्रदाय करना एवं निर्माण से संबंधित है अतः मस्टररोल, रोजगार पंजी, परिसंपत्ति पंजी, मजदूरी एवं सामग्री भुगतान पंजी आदि पुस्तकों का संधारण भारत सरकार के परिचालन दिशानिर्देश अनुसार किया जाएगा।

#### 7.1.3 खातों में उपलब्ध राशि को केवल तभी खर्च किया जा सकता है जब उन कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हो। अगर



इस तरह की स्वीकृति से पहले कोई खर्च किया जाता है तो उसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगी।

7.1.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखापरीक्षा नियम, 2011 के नियम 3 (1) के तहत सामाजिक अंकेक्षण कराना क्रियान्वयन एजेंसियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

7.1.5 क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का किसी अन्य मद में या कार्य में उपयोग नहीं किया गया है। अन्य मदों/कार्यों में उपयोग किए जाने पर इसे अनियमित माना जाएगा और संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 लेखा शीर्ष तथा लेखों की सारणी

योजनान्तर्गत प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा शीर्षों का वर्गीकरण तथा लेखांकन 'परिशिष्ट-2' में प्रस्तुत सारणी अनुसार किया जाएगा।

7.3 रोकड़ का सत्यापन :

7.3.1 संचित अधिकारी द्वारा अपनी रोकड़ बही में की गई सभी प्रविष्टियों की दैनिक जांच की जाएगी तथा प्रविष्टियों पर लघु हस्ताक्षर के साथ अंतिम प्रविष्टि पर दिनांकित हस्ताक्षर किए जाएंगे। मासिक लेखों का सत्यापन आगामी माह के 10 तारीख तक किया जाएगा।

7.3.2 अधिकारी द्वारा किये जाने वाले सत्यापन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं :-

(1) व्हाऊचरों में दर्शाई गई राशि की प्रत्येक प्रविष्टि का प्रभारित कुल राशि से मिलान किया जाएगा और उसी समय यह भी देखा होगा कि उनके द्वारा अभिलेखित भुगतान आदेश व्हाऊचर पर अंकित है एवं स्वयं अथवा प्राधिकृत अधीनस्थ के हस्ताक्षर का संचित प्रमाण पत्र अंकित है।

(2) भुगतान पक्ष में व्हाऊचरों की प्रविष्टियों की जांच करते समय देखा जाएगा कि व्हाऊचरों में दर्शाई गई सभी कटौतियों की प्रविष्टि रोकड़ बही के प्राप्त पक्ष में भी कर दी गई है।

7.3.3 बैंक को प्रेषित की गई राशि की प्रत्येक प्रविष्टि का मिलान बैंक जमा पर्ची एवं बैंक पास बुक से करना होगा एवं यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राशि वास्तव में बैंक खाते में जमा हो गई है।

7.3.4 रोकड़ बही के बैंक शेष तथा बैंक खाते के शेष का मिलान होना चाहिये। यदि रोकड़ बही के शेष और बैंक खाते के शेष में कोई अंतर हो तो उसके मिलान के लिये बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement) तैयार किया जाएगा।

7.3.5 रोकड़ बही की प्रत्येक प्रविष्टि संक्षिप्त एवं स्पष्ट होनी चाहिये। उसमें दिनांक, व्हाऊचर का क्रमांक एवं कार्य का नाम और लेन-देन की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण दिया जाना होगा।

7.3.6 रोकड़ बही में लेन-देन अनिवार्य रूप से घटनाक्रम के अनुसार ही प्रविष्टि किया जाना होगा।

7.3.7 भुगतान हेतु व्हाऊचरों को प्रतिमाह अलग श्रृंखला में क्रमानुसार क्रमांकित किया जाना चाहिये और रोकड़ बही में लेनदेन की प्रविष्टि के साथ ही व्हाऊचर पर सरल क्रमांक अंकित किया जाना होगा।

7.3.8 सभी भुगतानों को अनिवार्य रूप से उस कार्य अथवा सेवा, जिनके लिये भुगतान किया गया है, को डेबिट किया जाना होगा।

7.3.9 रोकड़ बही के पृष्ठों पर पृष्ठ क्रमांक अंकित होने चाहिये एवं प्रमाणीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा होना चाहिए।

7.3.10 रोकड़ बही की कोई भी पंक्ति खाली नहीं छोड़ी जावे। यदि कोई पृष्ठ आधा उपयोगित होता है और शेष पृष्ठ खाली छूट गया है तो खाली जगह को निरस्त करने के लिये तिरछी रेखा खींच देना होगा ताकि उसके बाद कोई भी प्रविष्टि किए जाने की संभावना न रहे।

- 7.3.11 प्रविष्टियों में प्रक्षेप (Insertion) यथा संभव नहीं किया जावे। यदि दो पंक्तियों के मध्य प्रविष्टि करना या कुछ जोड़ना अथवा पूर्व में की गई दो प्रविष्टियों के मध्य प्रक्षेप करना आवश्यक हो तो ऐसी प्रविष्टि या प्रक्षेप सदैव अधिकारी के दिनांकित लघु हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होगा।
- 7.4 यदि धनादेश (चेक) को निरस्त किया जाना आवश्यक हो
- 7.4.1 ऐसे प्रकरण में जहां धनादेश जारी नहीं किया गया है, धनादेश पर ही दिनांकित हस्ताक्षर सहित "निरस्त" अभिलेखित किया जाना होगा।
- 7.4.2 यदि धनादेश जारी हो चुका है तो उसे वापिस लेकर निरस्त किये जाने का उल्लेख मूल धनादेश पर इस प्रकार किया जाना होगा कि मूल धनादेश डिफेस (Deface) हो जाए। रोकड़ बही (Cash Book) में की गई पूर्व प्रविष्टियों के विपरीत प्रविष्टियां भी किया जाना होगा।
- 7.4.3 यदि धनादेश, धनादेश काटने वाले अधिकारी के पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में रोकड़ बही में निरस्तीकरण की प्रविष्टियां करने के पूर्व बैंक से भुगतान न होने (Non-Payment) एवं भुगतान रोक देने (Stop Payment) का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
- 7.4.4 यदि धनादेश का भुगतान किसी भी कारण से जारी करने की तिथि से छः माह तक नहीं हो पाता और उसे नया धनादेश जारी करने के लिये समर्पित भी नहीं किया जाता है तो कड़िका 7.4.3 में दर्शाए गये प्रक्रिया के अनुसार उसे निरस्त कर दिया जाना होगा। चेक से संबंधित राशि रोकड़ बही में राइट बैक (Write Back) किया जाना होगा।
- 7.4.5 नवीनीकरण के लिये प्राप्त कालातीत (Time Barred) धनादेश को नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। इस कार्य हेतु रोकड़ बही में संशोधन न करते हुये, रोकड़ बही में लाल स्याही से उपयुक्त प्रविष्टि किया जाना होगा। कालातीत चेक, धनादेश जारी करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर से, निरस्त किया जाना होगा। निरस्त किये गये धनादेश को उसके बदले में जारी किये गये धनादेश का क्लकचर माना जाना होगा। तथा नया धनादेश जारी करने का उल्लेख उस पर भी किया जाना होगा।
- 7.4.6 यदि खोए हुए धनादेश के बदले में नया धनादेश जारी करने के लिये आवेदन प्राप्त होता है तो नया धनादेश जारी करने के पूर्व बैंक से भुगतान न होने (Non-Payment) एवं भुगतान रोकने (Stop-Payment) के प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं रोकड़ बही में इसकी लाल स्याही से उपयुक्त प्रविष्टि किया जाना होगा। खोए हुये धनादेश के निरस्तीकरण, नवीन धनादेश जारी करने की टीप रोकड़ बही की मूल प्रविष्टि के सामने भी अंकित किया जाना होगा।
- 7.4.7 यदि खोए गए धनादेश पर भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो तो तत्काल संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए राशि की वसूली की जाये।
- 7.5 धनराशि की प्राप्ति
- 7.5.1 धनराशि प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के प्राप्ति कॉलम में ही अंकित किया जाये। स्थानीय बैंको द्वारा जारी किये गये बैंक धनादेश ड्राफ्टों के लिये, जब तक वे समाशोधित (Cleared) नहीं हो जाते, भुगतानकर्ता को अंतिम रसीद न दिया जाये।
- 7.5.2 प्राप्त की गई राशि की नियमानुसार रसीद दी जाए एवं उसी दिन अधिकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि राशि की प्राप्ति रोकड़ बही में अभिलेखित कर ली जाये।
- 7.5.3 अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि को आगामी कार्यदिवस में बैंक में जमा करना होगा।
- 7.6 अभिलेखों को सुरक्षित रखने की अवधि :-
- 7.6.1 अभिलेखों को सुरक्षित रखने की अवधि आगे दी गई तालिका में दर्शित है, लेकिन अभिलेखों का नष्ट करने से पूर्व निर्धारित अवधि के पश्चात् भी निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये।

- (i) यदि कार्य अपूर्ण है तो निर्धारित अवधि के पश्चात् भी अभिलेख सुरक्षित रखे जायेंगे।
- (ii) उन मामलों से संबंधित दस्तावेज जो कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत लंबित हैं, निर्धारित अवधि पश्चात् भी सुरक्षित रखे जाएंगे।
- (iii) कर्मचारियों की सेवा संबंधी दावे, दस्तावेज एवं व्यक्तिगत मामलों की जानकारी जिनका संबंध सेवा से है निर्धारित अवधि पश्चात् भी सुरक्षित रखे जाएंगे।
- (iv) दस्तावेजों को नष्ट करने के लिये आयुक्त से नष्ट किये जाने वाले दस्तावेजों के विवरण सहित स्वीकृति ली जानी चाहिये।
- (v) कोई भी लेखा-जोखा या दस्तावेज, जिसका अंकेक्षण महालेखाकार, स्थानीय निधि संपरीक्षा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना है, को नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका अंकेक्षण नहीं हो जाता और अंकेक्षण की आपत्तियां दूर नहीं कर ली जाती।
- (vi) उपरोक्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखने संबंधी सूची व्यापक या अंतिम नहीं है। कोई दस्तावेज, जिसकी भविष्य में कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी जिम्मेदारी ले और आयुक्त से विधिवत् आदेश प्राप्त कर लिये गये हो।

विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की न्यूनतम अवधि :-

क्र	दस्तावेजों का विवरण	सुरक्षित रखने का समय
1	रोकड़ बही	स्थायी
2	वेतन देयक एवं पावती पत्रक	स्थायी
3	यात्रा भत्ता देयक एवं पावती पत्रक	5 वर्ष
4	डाक टिकट से संबंधित लेखा	5 वर्ष
5	मृत स्कंध पंजी (Dead Stock)	स्थायी
6	प्रमाणक (व्हाउचर)	स्थायी
7	अग्रिम स्वीकृति संबंधी दस्तावेज	5 वर्ष
8	शासकीय आदेश	स्थायी
9	निविदाओं (Quotations) का तुलनात्मक पत्रक	स्थायी
10	माप पुस्तिका	स्थायी
11	जमा एवं अग्रिम पंजी (Register of Deposits & Advances)	स्थायी

## 8. लेखा परीक्षा

- 8.1 निधियों की लेखापरीक्षा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011" के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
देवाशीष दास, सचिव.

## परिशिष्ट-1

लेखा इकाईयों में संधारित की जाने वाली आवश्यक पंजियों का प्रारूप

प्रपत्र : 1

## रोकड़ बही (Cash Book)

कार्यालय का नाम ..... माह ..... वर्ष.....

## प्राप्ति पक्ष (डेबिट)

दिनांक	विवरण	व्हा. क्र.	लेजर फोलियो क्र.	राशि (नगद)	राशि (बैंक)	योग	लेखा शीर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8

## भुगतान पक्ष (क्रेडिट)

दिनांक	विवरण	व्हा. क्र.	लेजर फोलियो क्र.	राशि (नगद)	राशि (बैंक)	योग	लेखा शीर्ष
9	10	11	12	13	14	15	16

प्रपत्र : 2

## लेजर (खाता)

नाम खाता .....

माह..... वर्ष.....

दिनांक	विवरण	रो.ब. फोलियो क्र.	नाम खाता (डे.)	जमा खाता (क्रे.)	शेष राशि
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र : 3

## तुलन पत्र (Trial Balance)

कार्यालय का नाम .....

(दिनांक ..... की स्थिति में)

क्रमांक	विवरण	ले.फो. क्र.	राशि (डे.)	राशि (क्रे.)
1	2	3	4	5

प्रपत्र : 4

## बैंक समाशोधन पत्र

## Bank Reconciliation Statement

जिला /जनपद/ ग्राम पंचायत/एजेंसी का नाम .....

(दिनांक ..... की स्थिति में)

बैंक का नाम (बैंक कोड) .....

IFSC कोड .....

खाता क्रमांक .....

विवरण	राशि
(अ) रोकड़ बही (कैश बुक) के अनुसार शेष	
जोड़ें	
(i) बैंक में सीधे जमा चेक/नगद/ड्राफ्ट	
(ii) बैंक द्वारा जारी ब्याज जिसकी प्रविष्टि नहीं हुई है	
(iii) जारी चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए	
(iv)	
योग (ब)	
घटाएँ	
(i) बैंक द्वारा विकलित प्रभार शुल्क	
(ii) बैंक में जमा चेक जो क्रेडिट नहीं किए गए	
(iii)	
योग (स)	
(ब) बैंक विवरणिका (पास बुक) के अनुसार शेष (अ + ब - स)	

प्रपत्र -5

संस्था का नाम.....

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

अवधि ..... से ..... तक

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
1. प्रारंभिक शेष		1. एजेंसियों को अग्रिम	
(अ) हस्तगत रोकड़ (संस्था में)		(अ) जिला पंचायत	
(ब) बैंक शेष		(ब) जनपद पंचायत	
(स) एजेंसी के पास शेष		(स) ग्राम पंचायत	
2. अनुदान की प्राप्ति *		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(अ) भारत सरकार से		2. योजना पर व्यय	
(ब) राज्य सरकार से		(अ) जिला पंचायत	
(स) अन्य प्राप्ति		(ब) जनपद पंचायत	
3. ब्याज प्राप्ति		(स) ग्राम पंचायत	
(अ) राज्य स्तर पर		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(ब) जिला पंचायत स्तर पर		3. जारी अनुदान	
(स) जनपद पंचायत स्तर पर		(अ) जिला पंचायत	
(द) क्रियान्वयन एजेंसी स्तर पर		(ब) जनपद पंचायत	
4. विविध		(स) ग्राम पंचायत	
(अ) राज्य स्तर पर		(द) अन्य क्रियान्वयन एजेंसी	
(ब) जिला पंचायत स्तर पर		4. प्रशासनिक/ अन्य व्यय	
5. अग्रिम/ ऋण / अनुदान की वापसी		(अ) वेतन/मानदेय	
(अ) जिला पंचायतों से		(ब) अंकेक्षण शुल्क	
(ब) जनपद /ग्राम पंचायतों से		(स)	
(स) अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों से		(द)	
		5. अंतिम शेष राशि	
		(अ) हस्तगत रोकड़	
		(ब) बैंक शेष	
		(स) एजेंसी के पास शेष	
योग		योग	

प्रपत्र : 6

**चिट्ठा (Balance Sheet)**

कार्यालय का नाम .....

(दिनांक ..... की स्थिति में)

दायित्व	राशि	संपत्ति	राशि
1	2	3	4
सामान्य निधि		स्थायी सम्पत्ति	
प्रारंभिक शेष -		अग्रिम	
(+) वर्ष में प्राप्त		रोकड़, बैंक शेष	
(-) यदि कुछ हो		हस्तगत रोकड़	
		बैंक शेष	
अन्य दायित्व		अन्य संपत्तियाँ	
(अ)			
(ब)			
(स)			
(द)			
योग		योग	

**(परिशिष्ट-2)**  
**लेखों की सारणी (लेखांकन एवं वर्गीकरण)**

लेखांकन			
क्र	डेबिट	क्रेडिट	लेखा शीर्ष क्रमांक
1.	निधि (प्राप्ति)		
1.01		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि में भारत सरकार से प्राप्त राशि	1.01 राज्य परिषद्
1.02		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि में राज्य शासन से प्राप्त राशि	1.02 राज्य परिषद्
1.03	छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि (केन्द्रीय अंश)		1.03 राज्य परिषद्
1.04	छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि (राज्य अंश)		1.04 राज्य परिषद्
1.05		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि (केन्द्रीय अंश)	1.05 एडीपीसी
1.06		छत्तीसगढ़ रोजगार गारंटी निधि से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि (राज्य अंश)	1.06 एडीपीसी
1.07		भारत सरकार से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.07 एडीपीसी
1.08		राज्य शासन से जिला रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.08 एडीपीसी
1.09	जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि को स्थानांतरित राशि		1.09 एडीपीसी
1.10	जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि (ग्राम पंचायत) को स्थानांतरित राशि		1.10 एडीपीसी
1.11		जिला रोजगार गारंटी निधि से जनपद रोजगार गारंटी निधि में प्राप्त राशि	1.11 पी.ओ
1.12	जनपद रोजगार गारंटी निधि से रोजगार गारंटी निधि (ग्राम पंचायत) को स्थानांतरित राशि		1.12 पी.ओ
1.13		जिला रोजगार गारंटी निधि से रोजगारगारंटी निधि (ग्राम पंचायत) में प्राप्त राशि	1.13 जी.पी
1.14		जनपद रोजगार गारंटी निधि से रोजगारगारंटी निधि (ग्राम	1.14 जी.पी



		पंचायत) में प्राप्त राशि		
1.15		सृजित हुई प्रासंगिक (इंसीडेंटल) निधि (1) बैंक से प्राप्त ब्याज (2) विविध प्राप्तियां	1.15	सभी संबंधित
		प्रासंगिक निधि का योग		
2.	प्रेषण की जाने वाली कटौतियां			
2.1		कर्मचारियों से प्रेषण योग्य कटौतियां	2.01	सभी संबंधित
3.	पुनर्भुगतान योग्य जमा			
3.1		विविध जमा	3.01	सभी संबंधित
4	योजना क्रियान्वयन (व्यय)			
	प्रत्यक्ष व्यय			
4.1	मजदूरी - अकुशल श्रमिक (केन्द्रीय अंश)		4.01	पीओ/जीपी
4.2	मजदूरी - अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक (केन्द्रीय अंश)		4.02	पीओ/जीपी
4.3	मजदूरी - अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक (राज्य अंश)		4.03	पीओ/जीपी
	कुल मजदूरी - अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक			
4.4	सामग्री (केन्द्रीय अंश)		4.04	पीओ/जीपी
4.5	सामग्री (राज्य अंश)		4.05	पीओ/जीपी
	कुल सामग्री			
	आकस्मिक व्यय (केन्द्रीय अंश)			
4.6	श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाएं		4.06	पीओ/जीपी
4.7	श्रमिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान		4.07	पीओ/जीपी
4.8	श्रमिकों का चिकित्सा व्यय		4.08	पीओ/जीपी
	कुल आकस्मिक व्यय (केन्द्रीय अंश)			
	प्रत्यक्ष व्यय का योग		/	
5.	बेरोजगारी भत्ता		5.01	जी.पी
6.	सामाजिक सुरक्षा गतिविधियां		6.01	पीओ/एडीपीसी
7.	अन्य योजना व्यय			
7.1	संचार एवं प्रचार व्यय		7.01	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.2	योजना एवं तकनीकी सहायता व्यय		7.02	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.3	प्रशिक्षण व्यय		7.03	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.4	पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यय		7.04	राज्य परिषद् / एडीपीसी
7.5	लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय		7.05	राज्य परिषद् / एडीपीसी

	अन्य योजना व्यय का योग			
8.	प्रशासनिक व्यय			
8.1	वेतन एवं भत्ते i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.01	सभी संबंधित
8.2	यात्रा व्यय i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.02	सभी संबंधित
8.3	चिकित्सा व्यय i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग		8.03	सभी संबंधित
	आकस्मिक व्यय			
8.4	पी.ओ.एल.		8.04	सभी संबंधित
8.5	वाहनों का किराया प्रभार		8.05	सभी संबंधित
8.6	छपाई एवं लेखन सामग्री		8.06	सभी संबंधित
8.7	फोटोकॉपी एवं टंकण		8.07	सभी संबंधित
8.8	डाक एवं कोरियर		8.08	सभी संबंधित
8.9	बैंक प्रभार		8.09	सभी संबंधित
8.10	अन्य व्यय		8.10	सभी संबंधित
	कुल आकस्मिक व्यय i. केन्द्रीय अंश ii. राज्य अंश योग			
	प्रशासनिक व्यय का योग			
9.	पूँजीगत व्यय			
9.1	परिसंपत्तियों का क्रय		9.01	सभी संबंधित
10	वसूली योग्य अग्रिम			
10.1	अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों को अग्रिम		10.01	पी.ओ
10.2	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		10.02	सभी संबंधित
10.3	कर्मचारियों से वसूली योग्य		10.03	सभी संबंधित
10.4	कर्मचारियों का अस्थाई अग्रिम		10.04	जी.पी
	वसूली योग्य अग्रिमों का योग			
11.	शेकड़ एवं बैंक शेष			
11.1	शेकड़ शेष i. केन्द्रीय निधि ii. राज्य निधि योग		11.01	सभी संबंधित
11.2	बैंक शेष i. केन्द्रीय निधि ii. राज्य निधि		11.02	सभी संबंधित

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक/483/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	धुमा प.ह.नं. 26/34	3.625	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	कसही जलाशय के डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/4444/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	जंगलपुर प. ह. नं. 16	3.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	गहिराभेड़ी जलाशय के अंतर्गत डुबान एवं नहर नाली निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/4446/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रामपुर प. ह. नं. 21	0.347	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बैराज के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 4 अप्रैल 2012

क्रमांक 19/क/अविअ./भू.अ./अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	सरायपाली	गनियारीपाली	2.69	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	सिंगबहाल जलाशय योजना उलट निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अत्तरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2012

प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्डारोड	उमरखोही प.ह.नं. 34	0.554	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्डारोड.	आर. एम. के. के. मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2012

प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	केनाडाड प.ह.नं. 2	5.737	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2012

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	केनाडाड प.ह.नं. 2	0.945	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2012

प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझगवां प.ह.नं. 2	1.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण क्रमांक 4 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2012

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझगावां प.ह.नं. 2	1.709	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्डुरोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण क्रमांक 3 हे.ड.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./13/अ-82/वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा रकबा नं. (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	ताराशिव प. ह. नं. 13	665 0.072 663/2 0.073 634 0.072 663/1 0.073 662 0.162	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिये कृषि भूमि का योग्य क्षेत्र भू-अर्जन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			653	0.040	
			643/3	0.134	
			642	0.133	
			636	0.073	
			643/2	0.134	
			623	0.061	
			615/3	0.287	
			615/4	0.162	
			615/6	0.080	
			615/2	0.337	
			615/5	0.138	
			615/1	0.190	
			640/1	0.158	
			641	0.210	
			643/4	0.020	
			625	0.060	
			626/1	0.040	
			626/2	0.133	
			638/1	0.174	
			644, 646	0.182	
			652	0.024	
			660/1	0.295	
			660/2	0.300	
			624	0.040	
योग			29	3.857	

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./14/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा रकबा नं. (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	खम्हरिया प. ह. नं. 11	116/3	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			116/19		
			116/21		





रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./15/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	के द्वारा	का वर्णन
			खसरा नं.	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	बहेसर प. ह. नं. 17	470/19	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			481/4		
			578		
			571/1		
			573/1		
			563/2		
			562/1		
			562/2		
			573/2		
			576/2		
			579		
			580		
			581/2		
			582		
			472		
			513		
			553		
			583		
			504		
			585		
			507		
			508		
			503/1-2		
			501		
			502		
			515/1		
			515/2		
			515/3		
			515/4		
			515/5		
			515/6		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			515/7	0.340	
			481/1	0.202	
			483	0.182	
			577/2	0.125	
			477	0.364	
			471/14	0.060	
			470/3	0.198	
			470/6	0.045	
			470/16	0.405	
			478	0.093	
			471/1-3-4	0.206	
			577/1, 2, 3	0.156	
			577/4	0.156	
			477/4	0.014	
			481/2	0.134	
			471/2, 5	0.324	
			482	0.020	
		योग	48	9.851	

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	तुलसी प. ह. नं. 17	120/1	0.04	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			120/2	0.207		
			120/3	0.263		
			120/4	0.202		
			120/5	0.142		
			149/2	0.202		
			150	0.336		
	151	0.255				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			155/1	0.202	
			153	0.101	
			154	0.445	
			289/2	0.324	
			296/1	0.263	
			296/6	0.073	
			296/8	0.781	
			296/1	0.263	
			296/6	0.073	
			296/8	0.781	
			297/2	0.109	
			297/3	0.517	
			297/4	0.348	
			360/189	0.405	
			298/1	0.121	
			360/188	0.202	
			360/203	0.138	
			360/204	0.231	
			360/147	0.101	
			360/148	0.101	
			360/68	0.101	
			360/70	0.101	
			302/1	0.243	
			302/2	0.405	
			303/2	0.004	
			304/2	0.101	
			360/167	0.275	
			360/165	0.283	
			360/152	0.477	
			360/104	0.405	
			360/107	0.040	
			355/1	0.598	
			355/2	0.599	
			432	0.202	
			443/3	0.069	
			441	0.182	
			304/12	0.194	
			443/2	0.991	
			439/1	0.130	
			439/2	0.187	
			439/3	0.021	
			439/4	0.118	
			439/5	0.102	
			439/6	0.077	
			439/7	0.063	
			439/8	0.058	
			439/9	0.065	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

439/10	0.065
439/2	0.065
439/13	0.066
439/14	0.065
439/15	0.059
439/16	0.124
439/17	0.073
439/18	0.063
437	0.101
446/1	0.140
446/2	0.142
446/3	0.145
446/4	0.028
446/5	0.029
446/6	0.029
446/7	0.028
446/8	0.028
360/145, 360/111	0.405
360/112	0.202
298/2	0.138
298/3	0.060
443/1	0.101
360/169	0.182
305/1	0.125
360/164	0.202
289/1	0.089
302/6	0.073
431/2	0.141
431/4	0.175
356	1.215
296/7	0.101
447/1	0.202
440	0.101
121/4	0.413
360/156	0.101
360/1	0.805
360/168	0.202
36/3	0.203
22/2	2.024
36/1	0.202
36/2	0.101
36/4	0.040
35/2	2.656
34/1	0.206
304/6	0.142
304/8	0.284
304/9	0.134

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			301/1	0.101	
			299/1	0.121	
			299/3	0.074	
			299/5	0.109	
			299/6	0.081	
			299/7	0.202	
			297/4	0.202	
			299/2	0.105	
			299/4	0.202	
		योग	108	26.848	

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./17/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		के द्वारा	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
रायपुर	तिल्दा	बरतौरी	167/7	0.208	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
		प. ह. नं. 13	166/1	0.364		
			167/1	0.237		
			167/3	0.037		
			167/4	0.267		
			149/10	0.243		
			6	0.174		
			148	1.194		
			139/2	0.171		
			139/4	0.034		
			142/2-3	0.129		
			140/2	0.134		
			141/2	0.097		
			142/1	1.587		
			126	0.073		
			167/5	0.175		
			167/6	0.168		
			122/6	0.048		
			122/7	0.044		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			129	0.174	
			122/4	0.194	
			168	0.174	
			139/5	0.17	
			139/6	0.037	
			171/3	0.04	
			136/2	0.081	
			140/1	0.133	
			136/1	0.182	
			120/2	0.121	
			122/5	0.049	
			58/1, 59/3	0.045	
			179/3	0.081	
			122/2	0.194	
			120/1	0.121	
			139/1	0.223	
			139/7	0.069	
			127/2	0.057	
			122/1	0.19	
			166/3	0.052	
			166/2	0.061	
			141/1	0.117	
			167/2	0.209	
			167/8	0.33	
			130/3	0.299	
		योग	44	8.787	

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क.वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./18/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल			
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	तिल्दा	732/1	0.02	मुख्य महाप्रबंधक, जिराफा बजार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाइन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन
		प. ह. नं. 08	733/1	0.025		
			739	0.113		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			740	0.077	
			741	0.015	
			780	0.302	
			736/1	0.077	
			737/1	0.02	
			737/3	0.109	
			737/2	0.061	
			738	0.154	
			742	0.101	
			779	0.150	
			781	0.302	
			785/2	0.073	
			783	0.04	
			784	0.150	
			785/1	0.073	
			681	0.032	
			691	0.025	
			682/1	0.040	
			705/2	0.182	
			786/1	0.207	
			682/2	0.04	
			683/1	0.121	
			683/2	0.121	
			690/2	0.012	
			690/1	0.150	
			692/2	0.101	
			693	0.133	
			689	0.040	
			704	0.072	
			709	0.048	
			710/2	0.202	
			707	0.222	
			705/1	0.174	
			708	0.113	
			710/1	0.101	
			711/1	0.134	
			711/3	0.028	
			717/2	0.101	
			730/29	0.121	
			717/1	0.202	
			724/1	0.198	
			730/9	0.20	
			730/3	0.113	
			730/4	0.040	
			730/7	0.222	
			730/8	0.202	
			730/10	0.154	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			730/11	0.222	
			730/36	0.202	
			730/31	0.101	
			730/30	0.150	
			730/35	0.210	
			730/37	0.202	
			730/39	0.202	
			678	0.101	
			680	0.150	
			706	0.202	
			710/1	0.202	
			711/2	0.121	
			730/19	0.101	
			730/31	0.202	
			730/37	0.304	
		योग	57	7.450	

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./19/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन			अनुसूची		धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	गैतरा प. ह. नं. 11	129	0.214	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.)	औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
			381	0.004		
			375/4	0.061		
			375/5	0.465		
			376/2	0.121		
			375/1	0.348		
			375/2	0.809		
			375/3	0.304		
			376/1	0.243		
			183/3	0.202		
			375/14	0.921		
			375/15	0.304		
			376/5	0.121		
			376/6	0.243		
			183/4	0.263		
			92/1	0.109		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			95/1	0.197	
			102/1	0.344	
			92/2	0.032	
			132	0.032	
			130/2	0.226	
			130/1	0.558	
			128/1	0.773	
			53/1, 3, 4	0.052	
			104/1	0.118	
			52/1	0.350	
			103/2, 104/2,	0.040	
			105/1, 123/2		
			375/8	0.688	
			375/9	0.405	
			375/16	0.304	
			376/7	0.121	
			376/8	0.195	
		योग	29	9.167	

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./20/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
					(6)
रायपुर	तिल्दा	कोनारी	70/4-5-6-7-16	0.486	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर (छ.ग.) औद्योगिक क्षेत्र के एप्रोच रेल्वे लाईन निर्माण योजना हेतु भू-अर्जन.
		प. ह. नं. 11	76/1	0.507	
			77/1	0.744	
			411/2	0.113	
			412/1	0.101	
			412/2	0.024	
			412/3	0.255	
			76/2	0.508	
			77/2	0.405	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			78/1	0.096	
			78/2	0.060	
			78/4	0.060	
			89/4	0.281	
			78/3	0.065	
			78/5	0.072	
			89/1	0.282	
			81/1	0.060	
			411/1	0.324	
			412/4	0.182	
			395/1	0.247	
			89/2	0.080	
			461/1, 3, 395/1	0.465	
		योग	22	5.417	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 19 अप्रैल 2012

क्रमांक/4075/भू-अर्जन/2012.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-बेमेतरा

(ख) तहसील-बेरला

(ग) नगर/ग्राम-बोरिया, प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

1273

0.06

(1) (2)

1280 0.14

1276 0.07

1291 0.09

1287 0.03

1299/2 0.40

1301 0.27

1298/2 0.20

1304 0.58

1245 0.01

1250 0.12

1274 0.17

1281 0.03

1277 0.07

1286 0.07

1288 0.04

1302 0.10

1303 0.47

1309 0.34

1252 0.04

1248 0.04

1278 0.46

1275 0.11

1282 0.24

1289 0.03

(1)	(2)
1292	0.06
1300	0.24
1298/1	0.30
1310	0.18
1008	0.38
1251	0.07
1279	0.27
1284	0.13
1285	0.11
1290	0.05
1283	0.05
1306	0.20
1305	0.54
1341	0.18
1009	0.15
1249	0.09
योग	7.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तरकोरी, बोरिया जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रुति सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर  
(ख) तहसील-पेण्डारोड  
(ग) नगर/ग्राम-कोटखरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 एकड़

खसरा नम्बर रकबा  
(एकड़ में)

(1) (2)

314/1 1.00

योग 1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटखरी बगड़ी मार्ग पर तिपान नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 3 अप्रैल 2012

रा.प्र.क्र. 01 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कबीरधाम  
(ख) तहसील-सहसपुर लोहारा  
(ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, पहनं. 59  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
27/1	0.081	84/8	0.030
		85/2	0.040
		86/1	0.070
		86/2	0.040
योग 1	0.081	102/2	0.110
		102/3	0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहगांव जलाशय के नहर नाली निर्माण में अर्जन (पूरक).		102/7	0.060
		102/8	0.080
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कंवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.		102/10	0.040
		102/12	0.040
		102/26	0.080
		102/29	0.050
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		102/30	0.040
		588/3, 592/3	0.421
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़		592/1	0.250
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन		592/8	0.080
राजस्व विभाग		592/10	0.090
		592/11	0.010
		593/3	0.120
		593/4	0.080
रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012		593/7	0.100
		594/1	0.450
क्रमांक/93/भू.अ./अ.वि.अ./48 अ./82 वर्ष 2010-11.—		595/2	0.240
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		595/3	0.050
		595/4	0.340
		595/6	0.170
		595/7	0.290
		600/3	0.020
		601/2	0.099
		602/1	0.060
अनुसूची		603/1	0.040
		604/1, 604/2	0.010
(1) भूमि का वर्णन—		योग	34 3.710
(क) जिला-रायपुर			
(ख) तहसील-अभनपुर			
(ग) नगर/ग्राम-केन्द्री, प. ह. नं. 21			
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.710 हेक्टेयर			
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2)	
(1)	(2)		
88/3	0.010		
84/4	0.060		
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 मई 2012

क्रमांक 9398.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)  
(ख) तहसील-डभरा  
(ग) नगर/ग्राम-बाड़ादरहा, प. ह. नं. 02  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.622 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
231	0.016	690	0.187
240	0.130	696	0.259
257/4	0.036	700/2, 700/3	0.073
502	0.024	700/7	0.045
503/1	0.077	700/11, 700/12क	0.020
507/1, 508/1	0.487	700/13क	0.004
507/2	0.040	710/1	0.036
549/3	0.012	710/2	0.024
550/3	0.014	710/3	0.045
550/7	0.019	710/4	0.089
550/22	0.081	640/3	0.097
550/23	0.040	640/4	0.097
670/7	0.045	676	0.024
585/1	0.260	728/1	0.024
620/9	0.012	728/2	0.028
664/4	0.045	729/2	0.036
664/5	0.045	735/2	0.016
682/13क	0.051	748/5	0.032
682/13ग	0.023	774/1	0.178
686/4	0.024	774/3	0.182
		780/8	0.036
		780/11	0.024
		780/14	0.032
		780/16	0.032
		780/19	0.028
		780/20	0.032
		780/21	0.032
		811/8	0.810
		827/20	0.049
		829/5	0.020
		830/1च	0.024
		830/2च	0.045
		831/3	0.058
		831/8	0.040
		831/9	0.058
		831/10	0.036
		850/1	0.032
		850/6	0.053
		850/8	0.036
		850/13	0.032
		850/15	0.049
		850/16	0.024

(1)	(2)
855	0.040
योग	4.622
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्याविधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.	

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 मई 2012

क्रमांक 9401.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)  
(ख) तहसील-डभरा  
(ग) नगर/ग्राम-टुण्ड्री, प. ह. नं. 02  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.961 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

92/1	0.036
92/2	0.040
160/1	0.093
174/1	0.445
174/2	0.239
174/3	0.202
175/1	0.627
175/2	0.061

(1)	(2)
175/3	0.012
175/4	0.061
176/1	0.336
176/3	0.336
181/3	0.312
193/2	0.235
207/2	0.032
208/1	0.198
208/2	0.101
208/3	0.299
213/1	0.105
213/2	0.073
214	0.058
215/1	0.061
215/2	0.061
215/3	0.051
215/4	0.032
215/5	0.065
215/6	0.028
219/1	0.069
219/2	0.045
406/1	0.202
406/2	0.202
406/3	0.194
406/5	0.202
407/2	0.152
416	0.417
417/2	0.207
439/1	0.012
439/2	0.008
439/3	0.304
440/5	0.028

योग

5.961

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्याविधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं सचिव, उप-महानगर.

